I beg to move† :

"That the Bill to provide for the withdrawal of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh for the services of a part of the financial year 1968-69, be taken into consideration.".

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That the Bill to provide for the withdrawal of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh for the services of a part of the financial year 1968-69 be taken into consideration".

The motion was adopted

MR. DEPUTY-SPEAKER : We shall now take up clause-by-clause consideration.

The question is :

"That clauses 1, 2 and 3, the Schedule, the Enacting formula and the Title stand part of the Bill.".

The Motion was adopted

Clauses 1, 2 and 3, the Schedule, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill

SHRI K. C. PANT : Sir, I beg to move :

"That the Bill be passed."

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That the Bill be passed."

The motion was adopted

12.50 hrs.

UTTAR PRADESH APPROPRIATION BILL* 1968

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI K. C. PANT) : I beg to move for leave to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh for the services of the financial year 1967-68."

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh for the services of the Financial year 1967-68."

The motion was adopted

SHRI K. C. PANT : I introduce† the Bill.

I beg to move† :

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh for the services of the financial year 1967-68, be taken into consideration."

MR. DEPUTY-SPEAKER : Motion moved :

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh for the services of the financial year 1967-68, be taken into consideration."

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : अध्यक्ष महोदय दो तीन बातें में मंत्री महोदय के सामने रखना चाहता हूं । चूंकि उत्तर प्रदेश के शासन की जिम्मेदारी इन्होंने अब अपने हाथ में ली है, इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो कर-व्यवस्था है उसके ऊपर वह नये सिरे से सोचें और मालगुजारी या जिसको लगान कहते हैं, उस टैक्स को खत्म करने के लिए वह तत्काल कुछ कदम उठायें और राष्ट्रपति जी से अनुरोध करें—जब बिल पास हो जाये उसके बाद—कि वे तत्काल इस सम्बन्ध में कोई कानून पास करें । इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में

*Published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, section 2, dated 26-3-68.

†Introduced/moved with the recommendation of the President.

[श्री मधु लिमये]

जो संयुक्त विधायक दल की सरकार बनी थी जिसके हाथ में 8-9 महीने तक शासन की बागडोर रही उसके द्वारा स्वीकृत कार्यक्रम में लगान को खत्म करना एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। लेकिन मुझे खेद है कि चरण सिंह की सरकार ने इस कार्यक्रम पर अमल नहीं किया। . . .

एक **माननीय सदस्य** : खेद है।

श्री मधु लिमये : आपको भी खेद होना चाहिए। 21 साल में आपने भी नहीं किया और 8 महीने की हमारी सरकार ने भी नहीं किया। इसीलिए हमारे दल को फैसला करना पड़ा कि अब हम चरण सिंह की सरकार को सहयोग नहीं दे सकते हैं। हमारे सम्मेलन में यह फैसला किया गया था कि जब विधान सभा की बैठक होगी तो लगान को समाप्त करने के लिए हमारे सदस्यों के द्वारा पहल की जायेगी और उसमें अगर यह सरकार गिर भी जाती है तो उसकी भी हम परवाह नहीं करेंगे। आज मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश से, बल्कि समूचे देश से लगान खत्म करने के बारे में पहल करें। उत्तर प्रदेश की भी इनकी जिम्मेदारी है और केन्द्र की भी इनकी जिम्मेदारी है।

एक दूसरी बात मैं और कहना चाहता हूं। मैं मिर्जापुर के इलाके का दौरा कर रहा था तो रिहन्द में जो बिजली पैदा होती है उसके बारे में मुझे जो जानकारी मिली उससे बड़ा दुख हुआ। रिहन्द की बिजली घाटा सहकर बिरला जी को कारखाने के लिए सस्ते में दी जा रही है जबकि वहां के जो काश्तकार हैं उनको सस्ती बिजली देने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। यह बड़ा पुराना मामला है। मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री इसके बारे में खुलासा करें कि बिरला जी को सस्ती बिजली देने के बजाय काश्तकारों को सस्ती बिजली देने का इंतजाम किया जाए और शहरों और देहातों में बत्ती जलाने के लिए जो बिजली देने का काम किया जाता है उसके दाम भी घटायें।

एक बात मैं उत्तर प्रदेश के बारे में और कहना चाहता हूं। इस समय भूमिहीनों का एक बड़ा आंदोलन उत्तर प्रदेश में चल रहा है। वे चाहते हैं कि जो पड़ती जमीन है उसका बटवारा भूमिहीनों में किया जाय और विशेषकर जो हरिजन और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले आदिवासी हैं उनको इस जमीन के बटवारे में प्राथमिकता दी जाए।

उत्तर प्रदेश हमारा सीमावर्ती इलाका है। इसकी सीमा नैपाल से और तिब्बत से भी मिलती है। उत्तर प्रदेश की सीमा पर बहुत बड़ा तस्कर व्यापार चल रहा है। मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि वे इस सम्बन्ध में सख्त कार्यवाही करें। तस्कर व्यापार के बारे में इसी वक्त एक मामला उठा था कि सोना आयात होता है और जो चांदी है वह बाहर जा रही है। मंत्री महोदय को पता होगा कि ब्रिटिश ओवरसीज़ एयरवेज़ कारपोरेशन के द्वारा यहां पर तस्कर व्यापार के जरिये सोना लाने की कोशिश की गई, उनके ऊपर एक मुकदमा भी चल रहा है और आपने वह सोना जब्त भी किया है। बी०ओ०ए०सी० के बारे में मुझे एक जानकारी मिली है, वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। बी० ओ० ए० सी० ब्रिटेन की कम्पनी है। इसके हवाई जहाज हमारे देश में आते हैं। (**व्यवधान**)

आप सुन लीजिए, इससे देश का भला होगा। मैं यह बात कहकर ही समाप्त करूंगा।

ट्रैफिक मैनुअल्स कारगो रेगुलेशन्स, सेक्शन (के), इंडिया (4) से मैं यह ले रहा हूं : आप सुनें कि बी० ओ० ए० सी० का ट्रैफिक रेगुलेशन क्या कहता है :

Traffic Manual Section

Cargo Regulations (K) India (iv)

Transit

Officially, goods destined to or from South Africa are not permitted to transit India. However, consignment of negli-

gible value can be carried provided they are stored out of sight in inner-most part of aircraft holds. If the value of a consignment is sufficient to make risk of confiscation a serious matter, the sender must be informed and must give a written indemnity to the carrier against any action the Government of India may take.

इसका मतलब यह है कि हमारे कानूनों को तोड़ने का काम सीमा पर तस्कर व्यापारी कर रहे हैं, जो हवाई जहाज आ रहे हैं वह भी कर रहे हैं। सरकार इसके बारे में सख्त कार्यवाही करे और बी० ओ० ए० सी० का लाइसेन्स खत्म करे और जो उनका सोना सरकार ने जब्त किया है वह उनको न लौटाए।

SHRI K. C. PANT: Sir, I shall reply only to the relevant points in a few sentences. The first point raised by my hon. friend is with regard to land revenue. He has pleaded for abolition of land revenue, but he has himself said that the SVD Government, which was in power for 10 months was not able to push it through, although it was part of its programme. So, I do not think it is a matter on which he can put the blame on us. We shall wait for the new Government to come in and consider this matter. But I would request him to ask the farmer today whether it is more important for him to get land revenue abolished or to get the means to increase his production. After all, the incidence of land revenue is a few rupees per acre. Nowhere is it more than that and it has been the same for the last 30 years. On the other hand, if the farmer gets seeds, irrigation facilities and fertilisers, he can increase—the production per acre by perhaps Rs. 500 or even Rs. 1000 per acre. Obviously it is far more important that he should be given the means to increase his production rather than talk about land revenue, which incidentally gives the smaller farmer some proof of his title to the land, which is another important factor.

Secondly, with reference to the rates charged from Birla Aluminium Corporation in Mirzapur, this is an old matter. I find from the records that at the time this agreement was entered into, the rate charged was Rs. 175 per KW-year from this plant. In comparable terms, for Messrs Indian Aluminium Corporation at Hirakud, the rate charged was Rs. 120 per KW-year. For Messrs. Aluminium Production Company of India in Kerala the charge was Rs. 135 per KW-year. So, as compared to the comparbale plant at that stage, this was Rs. 175 as compared to Rs. 120 and 135. Therefore, it cannot be said to be cheaper.

12 HRS.

श्री मधु लिमये : मैं ने यह नहीं पूछा था मैं ने पूछा था कि काश्तकारों को किस रेट मे दे रहे हैं और ग्राहकों को किस रेट से दे रहे हैं? तुलना तो यह करनी चाहिए खेती में और कारखाने में।

SHRI K. C. PANT: With all respect, that it a larger question. But what is the comparable rate—it is certainly relevant—in the same industry with which they have to compete. I thought that was a relevant factor, particularly when power happens to be a raw material in the case of aluminium. I am in full sympathy with the hon. Member that the power rates should be reduced in UP. But I would remind my hon. friend, Shri Limyae that during the course of the SVD Government not only were the facilities that were given earlier for the extension of lines for energisation of tube wells in rural arears were reduced but the power rates were increased.

श्री मधु लिमये : आप ने दिवालियापन दिखाया सरकार का इसलिए ऐसा हुआ।

SHRI K. C. PANT: So, I am surprised that he should make this plea here. So far as landless people go, it is again surprising that during the last 9-10 months we have seen a strange thing in UP. We have seen the Government or the Cabinet deciding certain things. My hon. friend's party was included in that Government; it was a part of the government. But,

[Shri K. C. Pant].

they were carrying on an agitation against the same government in the the field. It is something new in democracy.

श्री मधु लिमये आंदोलन करने के काम में आप की पार्टी भी हिस्सा ले सकती थी। सरकार और संगठन में रिश्ता होना चाहिए लेकिन संगठन को सरकार का गुलाम नहीं बनना चाहिए।

SHRI K. C. PANT: The principle of joint responsibility is well-know to my hon. friend. I am surprised that he should have departed from the principle of joint responsibility in the matter of the Government of UP and I hope that other constituent parties in that government and other parties in the country will also realise what the joint responsibility of his party in this matter is. But I am only sorry that he did not succeeded in his efforts to get something for the landless. I am with him in this matter and I wish the Government had been able to provide land by passing an order. But leading an agitation against the government, when one is part of the government is something new to democracy.

श्री मधु लिमये : 21 साल में कुछ नहीं हुआ उस के लिए तो वह कुछ भी नहीं कह रहे हैं, 8-9 महीने में नहीं हुआ तो उस के बारे में चर्चा कर रहे हैं।

SHRI K. C. PANT: So far as the case of BOAC is concernd, it is not relevant here unless it is suggested that UP, as part of India, is vitally interested in this case. I am sure he does not want to press it here at this stage.

श्री मधु लिमये : वह ठीक है लेकिन आप जांच कराइये उस की। देश का कानून टूट रहा है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जांच करायेंगे।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh for the services of the financial year 1967-68 be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That clauses 1, 2, 3, the Schedule, the Enacting Formula and title stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 1, 2, 3, *the Schedule, the Enacting Formhla and the title were added to the Bill.*

SHRI K. C. PANT: I beg to move:

"That the Bill be passed"

The motion was adopted.

13.3 hrs.

The Lok Sabha adjourned for lunch till Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at five minutes past Fourteen of the Clock.

[SHRIMATI LAKSHMIKANTHAMMA *in the Chair*]

ARMED FORCES (SPECIAL POWERS) BILL

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH): Mr. Chairman, I move:—

"That the Bill to continue the Armed Forces (Special Powers) Regulation, 1958, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The Bill, which is only an enabling Bill, seeks to continue in the territory of Nagaland State, for a further period, the Armed Forces (Special Powers) Regulation, 1958. It enables the Governor of Nagaland to declare whole or any part of the State as a disturbed' area, if in his opinion the disturbed or dangerous conditions prevailing in the area necessitate the use of armed forces in aid of the civil power. It is only when a declaration is made by the Governor in the official Gazette that the substantive provisions of the Regulation come into force.